हरि मोहन मंडल
बनाम
झारखंड राज्य
18 मार्च 2004
(न्यायमूर्ति दोराईस्वामी राजू एंव न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत)

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 109, 120 बी, 302 और 307:

हमला और हत्या–विचारण न्यायालय ने मुख्य आरोपी को धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और दो सह–अभियुक्तों को धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई–मुख्य आरोपी और सह–अभियुक्तों में से एक (अपीलकर्ता) को क्रमशः धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय ने अन्य सह–अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया – अपील पर, अभिनिर्धारितः अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोट से जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति पर हमला किया गया उसकी मृत्यु हो, लेकिन मृत्यु का कारण बनने का ज्ञान/इरादा और उसके निष्पादन में कुछ प्रत्यक्ष कृत्य शामिल हैं, धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है–चूँकि चश्मदीदों की गवाही में कोई कमी नहीं पाई गई और चोट पीड़ित के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगी थी, इसलिए धारा 307 सही ढंग से लागू की गई–हालाँकि, किसी भी पूर्व–ध्यान/हत्या की योजना के अभाव में, हिरासत की सजा घटाकर 5 साल कर दी गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, मृतक पीडब्ल्यू 1 और अन्य लोगों के साथ एक मिल में धान की भूसी निकालने गया था। वहां तीन आरोपी भी मौजूद थे। दोनों पक्षों में एक दूसरे से पहले धान की भूसी निकालने को लेकर विवाद हो गया था। इस प्रक्रिया में, अपीलकर्ता/सह–अभियुक्त ने जबरन उसका धान हॉलर में डाल दिया। जब मृतक ने विरोध किया तो मुख्य आरोपी ने चाकू से उसके पेट पर तीन–चार वार कर दिये, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच, एक सह–अभियुक्त/अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू 1 के सिर और आंख तथा एक अन्य पर चाकू से वार किया। सह–अभियुक्तों ने उस पर और हमला किया और अपराध करने के बाद सभी आरोपी भाग गये। इसकी शिकायत थाने में की गयी। पुलिस ने मामले की जांच की और 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 109/34 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट ने उनमें से तीन को अपराध करने के लिए दोषी पाया और मुख्य आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत और दो सह–अभियुक्तों को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। हालाँकि, इसने अन्य दो सह–अभियुक्तों को बरी कर दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपित और सह–अभियुक्त (अपीलकर्ता) के संबंध में दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की, लेकिन अन्य सह–अभियुक्तों के संबंध में साक्ष्य को अपर्याप्त पाया और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश दिया। इसलिए, दोषी अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय नहीं थे और इस प्रकार उनका बयान विश्वसनीय नहीं था। चूंकि घटना बिना किसी पूर्वचिन्तन के घटित हुई, इसलिए धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है और चूंकि अपीलकर्ता द्वारा पीडब्ल्यू 1 को पहुंचाई गई चोटें साधारण चोट की प्रकृति की थीं, इसलिए आजीवन कारावास की सजा देना कठोर था।

न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारितः 1.1. पीडब्लू 1 और 5 के साक्ष्य में किसी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है, जिससे अस्वीकृति की गारंटी दी जा सके।

1.2. यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा 307 आईपीसी में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत किया गया था। अपराधी बनने के प्रयास को अंतिम कार्य नहीं होना चाहिए। यह कानून में किसी दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है, यदि उसके क्रियान्वयन में किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई इरादा मौजूद हो। इसलिए, किसी आरोपी को धारा के तहत आरोप से बरी करना केवल इसलिए सही नहीं है क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें साधारण चोट की प्रकृति की थीं। यह परिस्थिति कि आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोट साधारण या मामूली थी, आईपीसी की धारा 307 के आवेदन को खारिज नहीं करेगी। निर्णायक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति।

महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल और अन्य, (1983) 2 एससीसी 28; आर. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2004) 2 एससी 78 और सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1965) एससी 843, संदर्भित।

1.3. पहली चोट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग पर थी और पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटों को ध्यान में रखते हुए, धारा 307 आईपीसी को सही ढंग से लागू किया गया है और आरोपी को इस धारा के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धान की भूसी निकालने के समय झगड़े हुए थे और हमले की कोई पूर्व–चिंतन या योजना नहीं थी, पांच साल की हिरासत की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या0 2004 की 348.

झारखंड उच्च न्यायालय रांची. के सी.आर.एल. 1997 का ए. क्रमांक 395 में दिए गए निर्णय एवं आदेश दिनांकित 21.2.2003 से अपील।

अपीलकर्ता की ओर से– श्री रवि प्रकाश गुप्ता और श्री सुशेन्द्र कुमार चैहान।

उत्तरदाता की ओर से– श्री मनीष मोहन एवं श्री अनिल कुमार झा।

न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया। अनुमति प्रदान की गई।

अपीलकर्ता को चार अन्य लोगों के साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में ''आईपीसी'') की धारा 302, 302 के साथ पठित धारा 120 बी, 307, 302 के साथ पठित धारा 109 के तहत दंडनीय अपराध के कारित करने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता हरि मोहन मंडल और दो अन्य आरोपी व्यक्तियों चंद्र मोहन और विजय को दोषी पाया। दो अन्य, गजाधर मंडल और रामेश्वर महतो को बरी कर दिया गया। जबकि चंद्रा मोहन को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। अभियुक्त–अपीलकर्ता हरि मोहन मंडल और विजय मंडल

को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अपील में, झारखंड उच्च न्यायालय की ऍक ख सदस्यी ने जहां तक आरोपी चंद्र मोहन और वर्तमान अपीलकर्ता का संबंध है, अपील को खारिज कर दिया, लेकिन आरोपी विजय मंडल को बरी करने का निर्देश दिया। जहां तक आरोपी अपीलकर्ता का संबंध है, ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा बरकरार रखी गई थी।

मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैः

घटना की तारीख यानी 12.02.1994 को सुबह लगभग 6.30 बजे, सूचनादाता अपने चाचा नारायण मंडल (बाद में 'मृतक' के रूप में वर्णित) और जनार्दन मंडल (पीडब्लू –1) के साथ गोड्डा पीरपैती पिच रोड स्थित सिकंदर महतो के मिल में धान की भूसी निकालने के लिए गया था। उनके आने के बाद तीनों आरोपी चंद्र मोहन मंडल, हरि मोहन मंडल और विजय मंडल भी वहां गये थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना धान का बोरा मिल में रखा था। पहले अपने धान की भूसी निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। अपीलकर्ता हरि मोहन मंडल ने जबरन उसका धान हॉलर में डाल दिया। जब मृतक नारायण मंडल ने इसका विरोध किया तो सभी आरोपियों ने उसके साथ गाली–गलौज की और आरोपी चंद्र मोहन मंडल ने अपनी कमर से चाकू निकाला और उसके पेट पर चाकू से 3–4 वार कर दिये। घायल होने पर मृतक नारायण मंडल गिर गया। जब जनार्दन मंडल (पीडब्लू–1) उसे बचाने गया, तो आरोपी हरि मोहन मंडल ने चंद्र मोहन मंडल से चाकू छीन लिया और उसके सिर और आंख पर वार कर दिया। वह भी घायल होकर गिर पड़ा। आरोपी विजय मंडल ने जनार्दन मंडल (पीडब्लू–1) की आंख पर ईंट मारकर हमला किया। अभियुक्त विजय मंडल द्वारा सूचनादाता गुड्डु कुमार (पीडब्लू–5) पर फेंकी गई ईंटें उसे नहीं लगीं। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गये। नारायण मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। घायल जनार्दन मंडल (पीडब्लू–1) को रिक्शा पर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मिल मालिक के पिता रामेश्वर महतो, सिकंदर महतो और जोगिंदर महतो (पीडब्लू–9) ने कथित घटना देखी। शोर मचाने पर ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। मुखबिर (पीडब्लू–5) ने अन्य लोगों की मदद से नारायण मंडल के शव को एक ट्रॉली पर रख दिया। मुखबिर गुड्डु कुमार मंडल (पीडब्लू–5) का फर्द बयान (एक्सटेंशन 4) एस.आई., आर.के. ब्रहमचारी (पीडब्लू–11) प्रभारी पदाधिकारी, गोड्डा थाना द्वारा दिनांक 12.02.1994 को सुबह 9.20 बजे पी.ओ. ग्राम पुनासिया, पी.एस. गोड्डा टाउन पर दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत धारा 302, 307 आईपीसी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। गजाधर मंडल और रामेश्वर महतो के खिलाफ धारा 302, 307, 109/34 आईपीसी के तहत पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।

आरोपों को सच साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया। ट्रायल कोर्ट ने घायल ए–1 और मुखबिर गुड्डु कुमार (पीडब्लू–5) के साक्ष्य को ठोस और विश्वसनीय पाया। उनके सबूतों पर भरोसा करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया, लेकिन पाया कि अभियोजन पक्ष ने जहां तक सह–अभियुक्त गजाधर मंडल और रामेश्वर महतो का संबंध है, अपना मामला स्थापित नहीं किया है और तदनुसार उन्हें बरी करने का निर्देश दिया।

मुकदमे के दौरान और अपील में, गवाहों के पक्षपातपूर्ण होने और विवाद की उत्पत्ति को कथित तौर पर दबाने के आधार पर चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर सवाल उठाए गए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस रुख को स्वीकार नहीं किया और साक्ष्य को ठोस पाया। घायल गवाह पीडब्लू–1 और अन्य

प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू–5 के साक्ष्यों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित कर लिया है, जहां तक आरोपी–अपीलकर्ता और सह–अभियुक्त चंद्र मोहन मंडल का सवाल है। लेकिन अभियुक्त विजय मंडल के संबंध में साक्ष्य अपर्याप्त पाया गया।

अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ने साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण नहीं किया है। तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय नहीं थे और उनका बयान भी विश्वसनीय नहीं था। इसके अलावा, घटना कथित तौर पर धान की भूसी को लेकर हुई और बिना किसी पूर्व योजना के कथित हमले किए गए। किसी भी घटना में, धारा 307 के तहत अपराध नहीं बनता है, जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है, पीडब्लू–1 को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, और आजीवन कारावास की सजा कठोर है।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का समर्थन किया और आगे कहा कि किए गए विश्लेषण और पहुंचाई गई चोटों की प्रकृति को देखते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हम पीडब्लू 1 और 5 के साक्ष्य में किसी भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं पाते है जिससे अस्वीकृति की गारंटी दी जा सके। अपीलकर्ता की यह दलील कि यह दोषों से भरी है, प्रमाणित नहीं की गई है। इसके विपरीत, इसमें सच्चाई की झलक भी है।

ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक परिदृश्य में, यह देखना होगा कि क्या धारा 307 आईपीसी लागू हाती है। सम्बन्धित प्रावधान इस प्रकार हैः

''जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, यदि उस कार्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे दस साल तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा और, और यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास, या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है।''

इस धारा के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि मौत का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। यद्यपि वास्तव में पहुंचाई गई चोट की प्रकृति अक्सर आरोपी के इरादे के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफी सहायता कर सकती है, ऐसे इरादे का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है, और यहां तक कि, कुछ मामलों में, वास्तविक घावों के लिए बिना किसी संदर्भ के भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। ऐसा कृत्य जहां तक हमला करने वाले व्यक्ति का संबंध है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में लगी चोट सामान्य परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या जानकारी के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत किया गया था। अपराधी बनने के प्रयास को अंतिम कार्य नहीं होना चाहिए। यह कानून में पर्याप्त है, अगर उसके क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई इरादा मौजूद हो।

धारा 307 के तहत किसी दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है यदि उसके क्रियान्वयन में किसी प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कोई इरादा मौजूद हो। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। यदि चोट मृत्यु का कारण बनने के घोषित उद्देश्य या इरादे से दी गई है, तो चोट की अनुष्ठान प्रकृति, सीमा या चरित्र या क्या ऐसी चोट वास्तव में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, वास्तव में ऐसे कारक हैं जो धारा 307 के तहत दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। आई.पी.सी. की यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। इसलिए, किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप से बरी करना सिर्फ इसलिए सही नहीं है क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें साधारण चोट की प्रकृति की थीं।

इस स्थिति को *महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल और अन्य, (1983) 2 एससीसी 28* और *आर. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, (2004) 2 सुप्रीम 78* में उजागर किया गया था।

सरजू प्रसाद बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1965) एससी 843 के मामले में पैरा 6 में यह देखा गया कि केवल यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा वास्तव में पहुंचाई गई चोट ने पीड़ित के किसी भी महत्वपूर्ण अंग को नहीं काटा है, अपने आप में धारा 307 के दायरे से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

क्या मारने का इरादा था या यह जानकारी थी कि मौत होगी, यह तथ्य का प्रश्न है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह परिस्थिति कि आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोट साधारण या मामूली थी, आईपीसी की धारा 307 की प्रयोज्यता को खारिज नहीं करेगी। निर्णायक प्रश्न इरादा या ज्ञान है, जैसा भी मामला हो, न कि चोट की प्रकृति।

डॉक्टर पीडब्लू–6 द्वारा पीडब्लू–1 पर देखी गई चोटें इस प्रकार हैं:

(ए) बाएं सुप्रा ऑर्बिटल क्षेत्र पर एक कटा हुआ घाव, जो रिसने की स्थिति में तिरछा है। आयाम 8 से.मी.×२ से.मी×2.5 से.मी.।

(बी) चेहरे के बाएं दाढ़ क्षेत्र पर 6 से.मी. × 2 से.मी. × 2.5 से.मी. रिसने की स्थिति में एक कटा हुआ घाव।

(सी) बाएं पटेलर क्षेत्र 6 से.मी. × 4.5 से.मी. पर एक घर्षण।

(डी) बाईं ओर दोनों आंखों की पलकों पर एक चोट 5 से.मी.×3 से.मी. और 4.5 से.मी.×2.5 से.मी.

(ई) एकाधिक साइट पर पढ़ने योग्य नहीं।

(एफ) व्यापक नेत्रश्लेष्मला रक्तस्राव के कारण पूरी बाईं आंख लाल हो गई थी

पहली चोट गंभीर बताई गई थी और अब तक की राय में चोट नं. 6 का संबंध है, आरक्षित रखा गया था।

पहली चोट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण अंग पर थी और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 को सही ढंग से लागू किया गया है। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धान की भूसी निकालने के समय विवाद हुआ था और हमले की कोई पूर्व योजना या पूर्व सोच नहीं थी, न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांच साल की

हिरासत की सजा पर्याप्त होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसमें विचार की गुंजाइश है, अपील अपराध की प्रकृति और परिणामस्वरूप सजा तक सीमित थी।

जहां तक दोषसिद्धि का सवाल है, अपील खारिज कर दी जाती है, लेकिन ऊपर बताए अनुसार सजा की सीमा तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

एस.के.एस.

अपील खारिज।

Certified that "This is word to word true revetting/revalidation of judgments done by Anita Kumari, 3rd Additional Civil Judge (Sr.Div.) Uttarakhand."